



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2016/कार्तिक 6, 1938

No. 2595]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2016/KARTIKA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2016

(आयकर)

**का. आ. 3346(अ).**—चूंकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान की सरकार के बीच अभिसमय का संलग्न संशोधनकारी प्रोटोकॉल [जिसे इसके बाद “उक्त प्रोटोकॉल” कहा गया है], अभिसमय के इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 के अनुसार कथित प्रोटोकॉल के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए 29 अक्टूबर, 2016 से लागू होगा;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान की सरकार के बीच अभिसमय के संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं.102/2016/फा.सं.506/69/81-एफटीडी-1]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध

**आय पर करों के संबंध में  
दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन  
को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार  
तथा जापान की सरकार  
के बीच अभिसमय  
का संशोधनकारी प्रोटोकॉल।**

भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान की सरकार,

24 फरवरी, 2006 को टोक्यो में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (इसके बाद “अभिसमय” कहा गया है) द्वारा यथा संशोधित 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने की इच्छा से,  
इस प्रकार सहमत हुए हैं:

**अनुच्छेद 1**

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 तथा 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“3. पैराग्राफ 2 के अनुबंधों में किसी बात के होते हुए, करार करने वाले राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला व्याज दूसरे संविदाकारी राष्ट्र में ही कराधीन होगा यदि:

- (क) व्याज, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण, या उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है; अथवा
- (ख) व्याज, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्याभूत, बीमित या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित ऋण-दावों के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, शब्दों, “केन्द्रीय बैंक” और उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था” का आशय:

- (क) जापान के मामले में:
  - (i) बैंक ऑफ जापान;
  - (ii) जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन;
  - (iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी;
  - (iv) निप्पोन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस;
  - (v) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी संविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमति के अनुसार जापान की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है;
- (ख) भारत के मामले में:
  - (i) भारतीय रिजर्व बैंक;
  - (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक;
  - (iii) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया;
  - (iv) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;

- (v) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी संविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमति के अनुसार भारत की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।”

## अनुच्छेद 2

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

### "अनुच्छेद 26

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, यदि ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता संविदाकारी राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार सम्बंधी, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक राज अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

### अनुच्छेद 3

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के बाद निम्नवत रूप से एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा:

#### “अनुच्छेद 26 क

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए अनुच्छेद 2 में शामिल तथा निम्नलिखित करों से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है:

(क) जापान में:

- (i) उपभोग कर;
- (ii) विरासत कर; और
- (iii) उपहार कर;

(ख) भारत में:

- (i) संपत्ति कर;
- (ii) उत्पादशुल्क;
- (iii) सेवा कर;
- (iv) बिक्री कर; और
- (v) मूल्य वर्धित कर;

(ग) कोई अन्य कर जिस पर संविदाकारी राज्यों की सरकारें सहमत हुई हों।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा खुद अपने करों के प्रवर्तन और वसूली

के लिए प्रयोज्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था जो दूसरे संविदाकारी राज्य को इस पैराग्राफ के तहत एक अनुरोध करने की शर्त को पूरी करता हो।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस संविदाकारी राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. पैराग्राफ 5 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किसी राजस्व दावे के संग्रहण में किसी संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य, जो, यदि दूसरे संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए थे, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार राजस्व दावे पर लागू समय-सीमा को निलंबित या हस्तक्षेप करने का प्रभाव होगा, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के तहत इस प्रकार का प्रभाव होगा। पहला उल्लिखित संविदाकारी राष्ट्र ऐसे कार्यों के बारे में दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को सूचित करेगा।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

- (क) पैराग्राफ 3 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा, जोकि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में है जोकि उस समय, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इसके संग्रहण का निवारण नहीं कर सका या
- (ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति के विपरीत हों;
- (ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- (घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस संविदाकारी राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

#### अनुच्छेद 4

1. यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्रों की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित होगा और इस प्रकार का अनुमोदन दर्शाते हुए राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान की तारीख के बाद तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 तथा 4 के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) जापान में:

(i) किसी कराधीन वर्ष के आधार पर लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी कराधीन वर्ष हेतु करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ii) किसी कराधीन वर्ष के आधार पर नहीं लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लगाए गए करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ख) भारत में:

(i) स्रोत पर रोक कर रखे गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद भुगतान या क्रेडिट की गई राशि के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ii) कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है।

3. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 26 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 द्वारा जोड़े गए अभिसमय के अनुच्छेद 26क के उपबंध, उस तारीख, जिस तारीख को कर लगाए गए या कराधीन वर्ष, जिससे कर संबंधित हैं, पर ध्यान दिए बिना, प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. यह प्रोटोकॉल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अभिसमय लागू रहता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में वर्ष 2015 के दिसम्बर माह के 11वें दिन जापानी, हिन्दी और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

जापान की  
सरकार की ओर से

(हसमुख अडिया)  
राजस्व सचिव

(केंजी हिरामत्सु)  
जापान के राजदूत

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2016

### INCOME-TAX

**S.O. 3346(E).**— Whereas the annexed Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income [hereinafter referred to as said “Protocol”] shall enter into force on the 29<sup>th</sup> day of October, 2016 in accordance with paragraph 1 of Article 4 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of said Protocol amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income shall be given effect to in the Union of India with effect from the 29<sup>th</sup> day of October, 2016.

[Notification No.102/2016 /F. No. 506/69/81-FTD-I]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.

ANNEXURE

### PROTOCOL

#### AMENDING THE CONVENTION

#### BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of Japan,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at New Delhi on 7th March, 1989, as amended by the Protocol signed at Tokyo on 24th February, 2006 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Have agreed as follows:

## ARTICLE 1

Paragraphs 3 and 4 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:

- (a) the interest is derived and beneficially owned by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, or the central bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government; or
- (b) the interest is derived and beneficially owned by a resident of that other Contracting State with respect to debt-claims guaranteed, insured or indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, or the central bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government.

4. For the purposes of paragraph 3, the terms “the central bank” and “financial institution wholly owned by that Government” mean:

- (a) in the case of Japan:
  - (i) the Bank of Japan;
  - (ii) the Japan Bank for International Cooperation;
  - (iii) the Japan International Cooperation Agency;
  - (iv) the Nippon Export and Investment Insurance; and
  - (v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States;
- (b) in the case of India:
  - (i) Reserve Bank of India;
  - (ii) Export-Import Bank of India;
  - (iii) General Insurance Corporation of India;
  - (iv) New India Assurance Company Limited; and
  - (v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of India as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States.”

## ARTICLE 2

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:



---

“Article 26

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political sub-divisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying Contracting State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

**ARTICLE 3**

A new Article shall be added after Article 26 of the Convention as follows:

## “Article 26A

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of the taxes covered by Article 2 and the following taxes imposed on behalf of the Contracting States, or of their political sub-divisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount:

- (a) in Japan:
  - (i) the consumption tax;
  - (ii) the inheritance tax; and
  - (iii) the gift tax;
- (b) in India:
  - (i) the wealth tax;
  - (ii) the excise duty;
  - (iii) the service tax;
  - (iv) the sales tax; and
  - (v) the value added tax;
- (c) any other tax agreed upon between the Governments of the Contracting States.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State that met the conditions allowing that other Contracting State to make a request under this paragraph.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or

4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, acts carried out by a Contracting State in the collection of a revenue claim accepted by that Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4, which, if they were carried out by the other Contracting State, would have the effect of suspending or interrupting the time limits applicable to the revenue claim according to the laws of that other Contracting State, shall have such effect under the laws of that other Contracting State. The first-mentioned Contracting State shall inform the other Contracting State about such acts.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or
- (b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to carry out measures which would be contrary to public policy;
- (c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”

#### ARTICLE 4

1. This Protocol shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.

2. The provisions of paragraphs 3 and 4 of Article 11 of the Convention, as amended by Article 1 of this Protocol shall have effect:

(a) in Japan:

(i) with respect to taxes levied on the basis of a taxable year, for taxes for any taxable years beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and

(ii) with respect to taxes not levied on the basis of a taxable year, for taxes levied on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and

(b) in India:

(i) with respect to taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and

(ii) with respect to taxes on income for any previous year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

3. The provisions of Article 26 of the Convention, as amended by Article 2 of this Protocol, and Article 26A of the Convention, as added by Article 3 of the Protocol, shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the date on which the taxes are levied or the taxable year to which the taxes relate.

4. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this eleventh day of December, 2015, in the Japanese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

Sd./-

(HASMUKH ADHIA)  
REVENUE SECRETARY

FOR THE GOVERNMENT OF  
JAPAN

Sd./-

(KENJI HIRAMATSU)  
AMBASSADOR OF JAPAN